तिब्बत देश

तिब्बत में जनउभार क्या बताता है ?

इस बार 10 मार्च का मौका तिब्बत के मामले में अभूतपूर्व रहा। राजधानी ल्हासा में सात–आठ भिक्षुओं के प्रदर्शन से शुरू हुआ चीन विरोधी असंतोष तीन दिन के भीतर पूरे तिब्बत में जंगल की आग की तरह फैल गया। तिब्बती आजादी की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों का मुंह बंद करने के लिए चीनी सेना और पुलिस ने कम से कम 140 तिब्बतियों को गोली से उड़ा दिया, एक हजार से अधिक लोग घायल हुए और हजारों लोगों को घरों और मठों से निकालकर गिरफ्तार कर लिया गया। 1959 और 1989 के बाद यह तीसरा मौका है जब तिब्बत की आजादी के लिए चीन के खिलाफ इतने विशाल पैमाने पर प्रदर्शन हुए।

इस साल अगस्त में होने वाले बीजिंग ओलंपिक के नशे में मस्त चीन सरकार के लिए यह तिब्बती आंदोलन एक भयंकर सदमे जैसा था जिसे चीनी शासकों ने पुलिस की बेरहम गोलियों के माध्यम से व्यक्त किया। लेकिन उनकी इस हेकड़ी ने पूरी दुनिया में तिब्बत के सवाल को नए सिरे से ऐसा खड़ा कर दिया है कि चीन सरकार के लिए इसका सामना करना मुश्किल हो गया है। निहत्थे तिब्बती युवाओं और भिक्षु–भिक्षुणियों पर चीनी अत्याचारों से आहत दर्जनों सरकारों, संसदों और असंख्य मानवाधिकार संगठनों और व्यक्तियों ने चीन सरकार की जमकर लानत–मलानत की है। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से लेकर विख्यात अभिनेताओं, कलाकारों और संगठनों ने बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इसके अलावा दुनिया भर में चीन सरकार के उपनिवेशवादी व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शनों और बयानों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है।

10 मार्च का दिन तिब्बत के इतिहास में एक खास स्थान रखता है। 1959 में इसी दिन तिब्बती जनता ने तिब्बत पर जबरन कब्जा जमाए बैठी चीनी सेना के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया था। लेकिन दुर्भाग्य से हथियारों और संख्या दोनो मामलों में तिब्बती जनता से कहीं अधिक ताकतवर होने के कारण चीनी सेना इस जनक्रान्ति को कुचलने में सफल रही थी। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए तिब्बत के शासक और धर्मगुरु दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। चीनी सेना की इस कार्रवाई में तब 80 हजार से ज्यादा तिब्बती मारे गए थे। और इसके साथ ही 1949 से तिब्बत पर कब्जा जमाने का चीनी अभियान भी पूरा हो गया था।

तबसे आज तक निर्वासन में और तिब्बत के भीतर चीनी नियंत्रण में रहने वाले तिब्बती 10 मार्च के दिन को तिब्बती जनक्रान्ति दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। तिब्बत के बाहर रहने वाले तिब्बती शरणार्थी दुनिया भर में फैले अपने समर्थकों की मदद से चीनी दूतावासों पर प्रदर्शन करके दुनिया का ध्यान तिब्बत की औपनिवेशिक हालत की ओर खींचते हैं। पिछले कुछ साल में यह समर्थन बहुत व्यापक और मुखर हुआ है। बल्कि यूरोप के देशों में तो इस दिन एक हजार से ज्यादा शहरों की नगरपालिकाएं अपने मेयर के कार्यालय पर आधिकारिक तौर से तिब्बती राष्ट्रध्वज लहराकर अपना समर्थन व्यक्त करती हैं।

लेकिन तिब्बत के भीतर चीनी उपनिवेशवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में तिब्बती नागरिकों को ऐसी सुविधा हासिल नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था में जहां किसी आम तिब्बती के घर या लाकेट से दलाई लामा की तस्वीर पकड़े जाने पर भी सात साल की जेल मिलती हो वहां किसी बड़े जनप्रदर्शन की कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद तिब्बती जनता चीनी कब्जे के खिलाफ अपना आंदोलन किसी न किसी तरह चलाए हुए है। हर साल वहां के शहरों, कस्बों, गांवों और मठों में किसी न किसी रूप में 10 मार्च के दिन तिब्बती भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कहीं पांच–दस लोग अचानक बाजार में भीड़ से निकल कर तिब्बत का झंडा लहराते हुए तिब्बत की आजादी और दलाई लामा के समर्थन में तब तक नारे लगाते रहते हैं जबतक चीनी पुलिस और उसके खुफिया एजेंट आकर उन्हें दबोच नहीं लेते। कई जगहों पर आजादी की यह आवाज रात में चोरी छिपे दीवारों पर लिखे गए नारों और पोस्टरों के माध्यम से व्यक्त होती है।

चप्पे–चप्पे पर चीनी पुलिस की मौजूदगी, गली बाजारों में लगाए गए वीडिओ कैमरों और हजारों खुफिया एजेंटों के कारण आम तौर पर ये प्रदर्शन सीमित संख्या वाले और क्षणिक होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे यह तो दर्ज कर ही जाते हैं कि चीन की गुलामी तिब्बती जनता को मंजूर नहीं है। इससे पहले 1989 में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे। लेकिन तब तिब्बत के गवर्नर हू जिंताओ ने चीनी सेना के टैंको की मदद से इन प्रदर्शनों को कुचल डाला था। खबरों पर चीनी सरकार के कब्जे और तिब्बत को विदेशियों की पहुंच से दूर रखने की चीनी नीति के वजह से तब दुनिया को इन प्रदर्शनों के बारे में बहुत देर से और केवल नाममात्र की जानकारी ही मिल पायी थी।

लेकिन इस बार नक्शा बहुत बदल चुका था। लाखों की संख्या में चीन से लाकर बसाए गए हान लोगों को दी गई इंटरनेट, मोबाइल फोन और शानदार सड़कों की सुविधा ने स्थानीय तिब्बती जनता के लिए संचार आसान कर दिया है। इनकी मदद से अब वे आपस में संपर्क करके संगठित हो सकते हैं और घटनाओं के फोटो, वीडियो फुटेज और जुबानी जानकारी पलक झपकते ही तिब्बत के दूसरे इलाकों और विदेशों में अपने समर्थकों तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि इस बार तिब्बती जनता का यह आंदोलन केवल ल्हासा या शिगात्से की गलियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि ढाई हजार किमी दूर कीर्ति मठ जैसे उन इलाकों तक भी फैल गया है जिन्हें चीन आसपास के चीनी प्रांतों का हिस्सा बना चुका है। पांच–दस प्रदर्शनकारियों की उम्मीद करने वाली चीनी पुलिस को इस बार पांच–पांच हजार तिब्बतियों के प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा।

पहले दस दिन के भीतर ही तिब्बत के पचास से ज्यादा स्थानों पर हुए इन प्रदर्शनों ने (इन स्थानों की जानकारी के लिए बैक कवर पर नक्शा देखें) चीन सरकार और दुनिया को दिखा दिया कि तिब्बती जनता के मन से आजादी की ललक खत्म नहीं हुई है। पचास साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भिक्षु क मोबाइल की तस्वीरें यूट्यूब और दुनिया भर के टीवी चैनलों के माध्यम से आम आदमी के घर तक पहुचीं। इन प्रदर्शनों ने चीन के इस प्रचार को भी नंगा कर दिया कि तिब्बती जनता चीन से खुश है और वह दलाई लामा को नफरत करती है। बल्कि इन प्रदर्शनों में जितने बड़े पैमाने पर दलाई लामा के फोटो और उनके समर्थन वाले नारे देखने सुनने को मिले उस सबने चीन सरकार और चीनी जनता दोनों को हैरान किया और सदमा पहुंचाया। इसी का नतीजा था कि बीजिंग में चीन के 22 वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने चीन सरकार की नाराजगी के परवाह न करते हुए दलाई लामा और तिब्बती जनता के समर्थन में बयान जारी किया। इस बयान में चीन सरकार से तिब्बती जनता के कष्टों को समझने और दलाई लामा के साथ बातचीत के रास्ते तिब्बती समस्या का हल निकालने की अपील की गई है। (विस्तृत बयान अगले अंक में)।

इस बार के तिब्बती प्रदर्शनों ने चीन सरकार के कई तरह के दूसरे दुष्प्रचार को भी करारा जवाब दिया है। एक तो यह कि 'टार' से बाहर के तिब्बती इलाकों की जनता ने बता दिया केवल 'टार' ही असली तिब्बत नहीं है। यह भी कि वे भी तिब्बती आजादी का सपना मन में पाले हुए हैं। और चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का सवाल अब यह भी बन गया है कि उसके अत्याचारों ने पूरी तिब्बती जनता को एकता के सूत्र में बांध दिया है। चीन के लिए अब यही रास्ता है कि वह तिब्बत से अपना उपनिवेशवादी कब्जा हटाए और सम्मानपूर्वक तिब्बत को आजादी दे।

विजय क्रान्ति

फोटो : विजय क्रान्ति

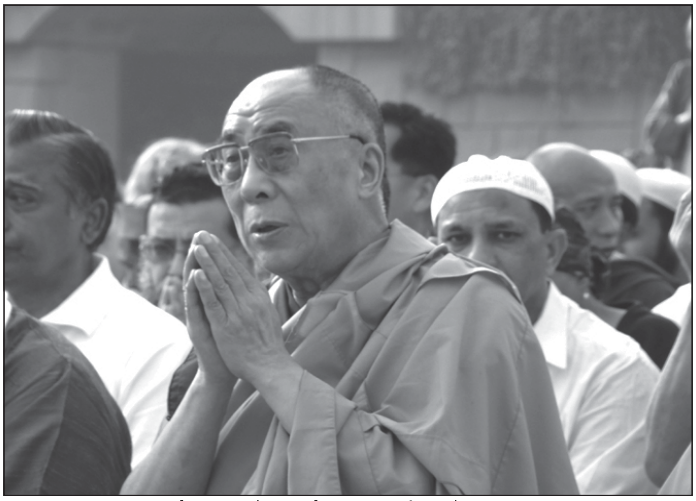

एक प्रार्थना सभा में दलाई लामा : अहिंसा में आस्था

''तिब्बती जनता अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखें'' – दलाई लामा

तिब्बती जनक्रान्ति की 49वीं वर्षगांठ पर दलाई लामा का संदेश

आज तिब्बत में दूरदर्शिता के अभाव में चीनी प्रशासन के अनेक कार्यकलापों के फलस्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। जनसंख्या स्थानांतरण की उनकी नीति के परिणाम स्वरूप गैर तिब्बती लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई है तथा तिब्बती अपने ही देश में नगण्य अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं।

10 मार्च 1959 को ल्हासा में तिब्बत के लोगों की शांतिपूर्ण जन क्रान्ति की 49वीं वर्षगांठ के अवसर मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूं तथा तिब्बत के उन वीर पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने अनगिनत कष्ट सहे और देश की खातिर बलिदान दिए। मैं वर्तमान में दमन तथा यातनाएं झेल रहे अपने तिब्बती बंधुओं के साथ एकजुटता प्रकट करता हूं। मैं तिब्बत में तथा तिब्बत से बाहर रह रहे तिब्बती–जनों, समर्थकों तथा सभी न्यायप्रिय लोगों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करता हूं।

लगभग 6 दशकों से चोलखासुम (ऊ–त्सांग, खम तथा आम्दो) के नाम से जाने जाते सारे तिब्बत में तिब्बती लोग भय, त्रास तथा संशय के वातावरण में चीनी दमन के अंतर्गत जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो भी अपनी धार्मिक भावनाओं, राष्ट्रीयता और विशिष्ट संस्कृति को कायम रखते हुए तिब्बती लोग स्वतंत्रता के प्रति मौलिक आकांक्षा को जीवित रखने में सफल रहे हैं। मैं तिब्बती लोगों के इन विशिष्ट गुणों तथा अदम्य साहस की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। मेरे लिए यह हर्ष का विषय भी हैं और गर्व का भी।

विश्व भर की अनेक सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने शांति और न्याय के प्रति अपनी रुचि के अनुसार तिब्बत के प्रश्न पर हमें निरंतर समर्थन दिया है। विशेषकर पिछले वर्ष में अनेक देशों की सरकारों ने हमारे पक्ष में कुछ ऐसे पग उठाए हैं जो स्पष्ट रूप में हमारा समर्थन करते हैं। उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा।

तिब्बत की समस्या बड़ी जटिल समस्या है। वास्तव में यह अनेकानेक पहलुओं से संबंधित है जैसे कि राजनीति, समाज, कानून, मानवाधिकार, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीय अस्मिता, अर्थव्यवस्था तथा प्रकृतिक पर्यावरण की स्थिति। इसलिए समस्या के समाधान के लिए एक विषद् दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सभी के हित समाहित हों न कि किसी एक पक्ष विशेष के। अतः हम हमेशा एक पारस्पारिक हितैषी नीति की ओर प्रतिबद्ध रहे हैं। अर्थात मध्यममार्गीय दृष्टिकोण। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने अनेक वर्षों से प्रयास किया है। 2002 से आज तक संबंधित समस्याओं के विचार के लिए मेरे प्रतिनिधियों ने 6 बार चीनी लोकतंत्र के अधिकारियों से वार्तालाप किया है। उक्त विचार विमर्श के फलस्वरूप कुछ शंकाएं दूर हुई हैं और दूसरे पक्ष के प्रति अपनी बात रखने का हमें अवसर मिला है। लेकिन मूल समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। पिछले एक साल में तिब्बत में यातनाओं और नृशंसता का क्रम बढ़ा है। इन दुखद घटनाओं के बावजूद मध्यवर्गीय नीति का अनुसरण करने तथा चीनी प्रशासन के साथ वार्तालाप जारी रखने की मेरी प्रतिबद्धता में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

चीनी गणतंत्र की प्रमुख चिंता है तिब्बत में उसकी वैधता का अभाव। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीनी प्रशासन को ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए जो तिब्बती जनता को आश्वस्त कर पाए तथा उसका विश्वास हासिल कर सके। यदि हम पारस्परिक सहमति के मार्ग पर चलते हुए आपसी मेल मिलाप प्राप्त कर सकें तो जैसे मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, मैं तिब्बत के लोगों का समर्थन अर्जित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा।

आज तिब्बत में दूरदर्शिता के अभाव में चीनी प्रशासन के अनेक कार्यकलापों के फलस्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। जनसंख्या स्थानांतरण की उनकी नीति के परिणाम स्वरूप गैर तिब्बती लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई है तथा तिब्बती अपने ही देश में नगण्य अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। इसके अतिरिक्त तिब्बत की भाषा, उसके रीति रिवाज़ तथा परंपराएं लुप्त हो रही हैं। इसलिए तिब्बती लोगों का बहुसंख्यक चीनी लोगों में विलय मोटे तौर पर होता जा रहा है। तिब्बत में दमन का क्रम जारी है; अनेक एवं अकथनीय प्रकार से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है; धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है; धार्मिक संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है। यह सब परिणाम है चीनी प्रशासन के तिब्बत लोगों के प्रति आदर भाव की अनुपस्थिति के कारण। राष्ट्रीयताओं के एकीकरण के मार्ग में चीनी प्रशासन जानबूझकर

ऐसे रोड़े अटका रहा है जो तिब्बतियों और चीनियों के बीच भेदभाव करते हैं। इसलिए मेरा चीनी प्रशासन से अनुरोध है कि वह तुरंत ऐसी नीतियों को निरस्त करे।

हालांकि उन प्रदेशों को जहां तिब्बती बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसे नाम दिए गए हैं जैसे कि 'स्वायत्त प्रदेश', 'स्वायत्त प्रीफेक्चर' तथा 'स्वायत्त काउंटी' आदि, परंतु वे नाम मात्र में ही स्वायत्त हैं। स्वायत्तता नाम की कोई चीज उन में है नहीं। उनके प्रशासक वे लोग हैं जो स्थानीय परिस्थितियों से बिलकुल परिचित नहीं हैं तथा जिनकी प्रेरणा मात्र वह वृत्ति है जिसे खुद माओ ने 'हान हेकड़ी' का नाम दिया था। मूल रूप से इस तथाकथित स्वायत्तता से अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं को कोई लाभ नहीं पहुंचा। ऐसी अनुपयुक्त नीतियां जिनका वस्तु स्थिति से कोई संबंध नहीं, न केवल छोटी राष्ट्रीयताओं को बड़ी हानि पहुंचा रही हैं बल्कि चीनी राष्ट्र की एकता और स्थिरता को भी। ऐसे में चीनी प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि वह वास्तविक मायनों में वह करे जिसे स्वयं देंग सियाओ पिंग ने 'तथ्यों में से सत्य का दोहन' कहा था।

जब भी मैं अंतर्राष्ट्रीय समाज के समक्ष तिब्बती लोगों के कल्याण की बात रखता हूं तो चीनी प्रशासन मेरी घोर निंदा करता है। जब तक हम किसी पारस्परिक लाभप्रद समाधान तक नहीं पहुंचते तब तक तिब्बती लोगों के बारे में स्वतंत्रता से विचार करना मेरा ऐतिहासिक तथा नैतिक कर्तव्य बनता है। सब जानते हैं कि मैं बहुत वर्षों से एक प्रकार से सेवानिवृत्ति की स्थिति में हूं क्योंकि तिब्बतियों के राजनीतिक नेतृत्व को अब सीधा तिब्बती प्रवासियों द्वारा चुना जाता है।

विशाल आर्थिक प्रगति के कारण चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यह स्वागत योग्य है। परंतु वैश्विक स्तर पर भी अब चीन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर आ गया है। दुनिया उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है यह देखने के लिए कि वर्तमान चीनी नेतृत्व अपने यहां समरसतापूर्ण समाज तथा शांतिपूर्ण प्रगति के अपने लक्ष्यों को कार्यान्वित करेगा। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मात्र आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं है। न्याय युक्त शासन, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। यदि चीन में स्थिरता चाहिए तो अनेक राष्ट्रीयताओं को अपनी अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए बराबर स्वतंत्र होना चाहिए।

6 मार्च, 2008 को राष्ट्रपति हू जिनताओ ने कहा है, ''तिब्बत की स्थिरता देश की स्थिरता से जुड़ी है और तिब्बत की सुरक्षा से देश की सुरक्षा।'' उन्होंने यह भी कहा कि चीनी नेतृत्व को तिब्बतियों के कल्याण को सुनिश्चित बनाना होगा, प्रदेशों तथा जातीय समूहों के काम को सुचारू बनाना होगा तथा सामाजिक समरसता और स्थिरता को बनाए रखना होगा। राष्ट्रपति हू का वक्तव्य तथ्यों के अनुसार है और हमें इसके कार्यान्वयन की प्रतीक्षा है।

इस वर्ष चीनी जनता बड़े गर्व और उत्सुकता के साथ ओलंपिक खेलों के शुरु होने की प्रतीक्षा कर रही है। मैंने शुरू से ही इस बात का समर्थन किया है कि चीन को ओलंपिक खेल करवाने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन, विशेषकर ओलंपिक, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समता और मैत्री आदि के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हैं, चीन को चाहिए कि वह एक अच्छे मेजबान की तरह इन स्वतंत्रताओं को प्रदान करे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समाज को चाहिए कि वह अपने खिलाड़ियों को भेजने के साथ–साथ चीनी प्रशासन को उपरोक्त बातों की याद भी दिलाए। मुझे पता चला है कि अनेक संसदें, व्यक्ति तथा गैर सरकारी संगठन विश्व भर में ऐसे कदम उठा रहे हैं जो इस अवसर पर चीन के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने को सक्षम बना सकें। मैं उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं। मैं यह भी जोर देकर कहता हूं कि खेल समाप्त होने के बाद वाली अवधि को बड़े ध्यान से जांचना होगा। निःसंदेह ओलंपिक खेल चीनी मानसिकता को प्रभावित करेंगे। इसलिए विश्व को चाहिए कि वह अपने सामूहिक प्रयासों के द्वारा खेल समाप्त होने के बाद भी चीन के भीतर सकारात्मक परिवर्तन संभव बनवाएं।

मैं इस अवसर पर तिब्बत में रह रहे तिब्बती लोगों की प्रतिबद्धता, साहस तथा दृढ़ निश्चय के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं और उनपर गर्व प्रकट करता हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि कानून के दायरे में रहते हुए अपने शांतिपूर्ण प्रयास जारी रखें ताकि तिब्बत समेत चीन की सभी अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं अपने उचित अधिकारों और हितों को प्राप्त कर सकें।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार तथा भारत के लोगों के प्रति विशेष रूप से तिब्बती शरणार्थियों को निरंतर सहायता तथा तिब्बत की समस्या के प्रति समर्थन के लिए आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं उन अनेक सरकारों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो लगातार तिब्बत की समस्या के प्रति सहानुभूति भरे ढंग से संबद्ध रहे हैं। मैं समस्त सत्वों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।

दलाई लामा
10 मार्च, 2008

तिब्बत की भाषा, रीति रिवाज़ तथा परंपराएं लुप्त हो रही हैं। इसलिए तिब्बती लोगों का बहुसंख्यक चीनी लोगों में विलय होता जा रहा है। तिब्बत में दमन का क्रम जारी है; अनेक प्रकार से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है; धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है; धार्मिक संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है। यह सब चीनी प्रशासन के तिब्बत लोगों के प्रति आदर भाव की अनुपस्थिति का परिणाम है इसलिए मेरा चीनी प्रशासन से अनुरोध है कि वह तुरंत ऐसी नीतियों को निरस्त करे।

फोटो : विजय क्रान्ति

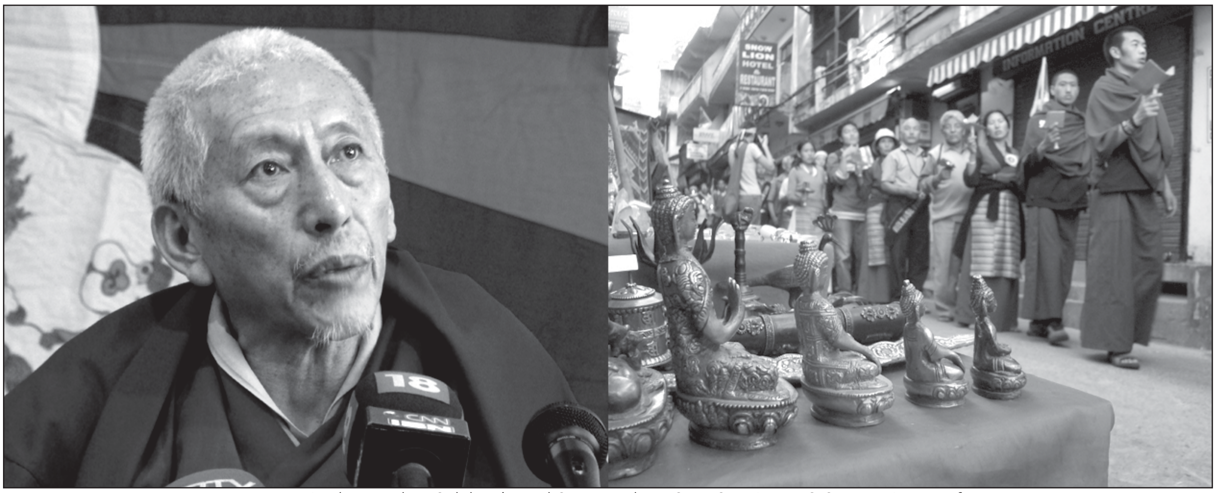

प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे और ज्योति यात्रा में शामिल तिब्बती : अनिश्चितकालीन संघर्ष

हमें चीनी कब्जे में रह रहे तिब्बतियों के साहस पर गर्व है

हम अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए तैयार रहें

22 मार्च को काशाग द्वारा जारी सार्वजनिक बयान

धर्मशाला में निर्वासन में रह रहे आम तिब्बती नागरिकों और बौद्ध धर्म संघ सदस्यों के माध्यम से तिब्बत के भीतर और बाहर रहने वाले भाई बहनों के लिए काशाग अपना यह वक्तय देना चाहता हैः –

तिब्बत में हाल ही में शुरू हुआ शांतिपूर्ण विरोध आंदोलन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि ऐतिहासिक महत्त्व का भी है। यह तिब्बतियों के अदम्य साहस और आंतरिक शक्ति का परिचायक है।

तिब्बत के भीतर की स्थिति को समझते हुए काशाग के सदस्य कहना चाहते हैं किः

1. तिब्बत में हाल ही में शुरू हुआ शांतिपूर्ण विरोध आंदोलन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि ऐतिहासिक महत्त्व का भी है। यह तिब्बतियों के अदम्य साहस और आंतरिक शक्ति का परिचायक है।

2. विरोध आंदोलन केवल ल्हासा और इसके निकटवर्ती इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा। यह तिब्बत के तीन पारम्परिक प्रांतों ऊ–त्सांग, आम्दो और खम के उन तमाम क्षेत्रों में फैल चुका है, जहां तिब्बती निवास करते हैं। यह किस बात का संकेतक है? सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि सभी तिब्बतियों की एक ही इच्छा है और वे अपने महान आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा के नेतृत्व में संगठित हैं। दूसरे, इस आंदोलन ने चीन के दुष्प्रचार को उजागर करते हुए तिब्बत के अंदर की वास्तविकता को सारी दुनिया के समक्ष ला खड़ा किया है। चीन यह दुष्प्रचार करता रहा है कि दलाई लामा के कुछेक अनुयायियों को छोड़कर तिब्बत में रहने वाले सभी तिब्बती चीन सरकार की नीतियों और विचारों के प्रति निष्ठावान हैं और तिब्बत धीरे–धीरे स्थायित्व की ओर अग्रसर है एवं यहां के लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक प्रगति से पूरी तरह संतुष्ट हैं।

3. यह आंदोलन परमपावन दलाई लामा के इस विचार को भी सही ठहराता है कि तिब्बत के तीनों पारम्परिक प्रांतों के निवासियों सहित सभी तिब्बतियों को एक ही स्वायत्त शासन के तहत रखना चाहिए।

4. चीन के नेताओं ने कहा है कि वे तिब्बत में प्रदर्शनों के खिलाफ 'जीवन और मृत्यु' की हद तक जाकर उसे कुचल देंगे। चीनी नेताओं के इस बयान ने उन की इस अंदरूनी असलियत को सामने ला दिया है कि ये नेता तिब्बतियों को चीन के बड़े परिवार का हिस्सा न मानकर उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं।

5. तिब्बतियों द्वारा हाल ही में शुरू किया गया शक्तिशाली और साहस भरा आंदोलन पिछले 49 वर्षों में हुए सभी आंदोलनों की तुलना में बड़ा है। चाहे हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मसले के रूप में देखें या घरेलू मसले के रूप में, इन विरोध प्रदर्शनों ने हमारे संघर्ष को ऐसे बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां कोई भी फैसला तिब्बतियों के अस्तित्व को ध्यान में रखकर ही करना होगा। साथ ही इन आंदोलनों के पीछे प्रमुख ताकत तिब्बतियों की चौथी पीढ़ी की है जिनका जन्म तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद हुआ है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमारा आंदोलन पीढ़ी–दर–पीढ़ी जारी रहेगा।

6. हाल की घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि तिब्बतियों की निष्ठा और संकल्प कितना दृढ़ है तथा उन्होंने किस तरह की कुर्बानियां दी हैं। इन घटनाओं ने हमें गौरवान्वित किया है। कशाग यही कहना चाहेगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी कुर्बानियां इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएंगी।

तिब्बती प्रशासन ने अभी तक क्या किया है?

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती

है कि निर्वासित तिब्बतियों को तिब्बत के भीतर रहने वाले अपने भाई बहनों के अदम्य साहस को पहचानना चाहिए तथा उसके अनुरूप एकजुटता प्रदर्शित करने वाले कदम उठाने चाहिएं, जिससे तिब्बतवासियों के आंदोलन के तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभों को बढ़ावा मिल सके। इसलिए निर्वासित तिब्बती पार्लियामेंट के नेतृत्व में एक उच्च–स्तरीय समिति गठित की गयी है, जिसकी कोशिश है कि तिब्बतियों के अलग–अलग किये जा रहे प्रयासों को सामूहिक रूप देकर संगठित किया जा सके। संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रवासी तिब्बतियों के इतिहास में यह एक नया कदम होगा। हमें उम्मीद है कि तिब्बती गैर सरकारी संगठनों, स्वायत्त इकाइयों और कल्याण संगठनों के साथ–साथ आम नागरिक भी समिति के निर्देशों पर अमल करेंगे।

8. तिब्बत में शुरू हुए चीनी दमन को देखते हुए परमपावन दलाई लामा ने अपनी हलकी अस्वस्थता के बावजूद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास जारी रखा है। विश्व के समान विचारधारा वाले नेताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पत्र लिखने के अलावा परमपावन दलाई लामा ने मीडिया को साक्षात्कार दिये हैं और विभिन्न देशों तथा वहां की जनता से तिब्बत समस्या में सहयोग पाने के लिए उनका आह्वान भी किया है। इसके अलावा, परमपावन दलाई लामा ने मौजूदा संकट को समाप्त करने तथा तिब्बतियों के संयुक्त पुण्यों को बढ़ावा देने के लिए डोल्मा एवं शेर–न्यिंग की प्रार्थना करने तथा ताद्रीन मंत्र पढ़ने की हमें सलाह दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्मशाला स्थित प्रधान तिब्बती मठ 'थेकचेन छ्योलिंग' स्थित मुख्य मंदिर में प्रार्थना सभा की अध्यक्षता भी की है।

हम सभी सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों तथा तिब्बती समर्थन समूहों को समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराकर एवं विदेशों में संचालित तिब्बती संगठनों के जरिये उनसे समर्थन की अपील कर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह कर रहे है। अमरीका और यूरोपीय संघ सहित पूर्वी और पश्चिमी देशों के वरिष्ठ नेताओं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, राजनीतिक दलों, सामाजिक सेवा संगठनों एवं विभिन्न धर्मों के शीर्षस्थ धर्माधिकारियों को तिब्बतियों के समर्थन में बयान जारी करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। काशाग ने इनसे तबतक अपना प्रभावकारी समर्थन जारी रखने की अपील की है जबतक तिब्बत मसले का अंतिम हल नहीं निकल जाता।

भविष्य के कदमों के लिए अपील

9. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की गयी आवश्यक अपील में शामिल मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

सिचुआन प्रांत के कीर्ति मठ नगर में तिब्बती प्रदर्शन के दौरान : अभूतपूर्व आंदोलन

क.) तिब्बत में हो रहे चीनी दमन और हत्याओं को तत्काल रोका जाए।

ख.) विरोध प्रदर्शनों के दौरान चीन सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये सभी लोगों को तत्काल रिहा किया जाए।

ग.) सभी घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। विभिन्न इलाकों में फंसे यात्रियों और पर्यटकों पर लगाये गए प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए तथा उन्हें पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

घ.) एक अंतर्राष्ट्रीय तथ्यान्वेशी प्रतिनिधिमंडल और तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टरों को बिना किसी प्रतिबंध के समूचे तिब्बत में जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

इन मांगों पर अमल के लिए हमारी सामूहिक ऊर्जा को सही और साझा दिशा देना आज के समय की मांग है।

10.) चीन सरकार ने तिब्बत के भीतर और बाहर रह रहे तिब्बतियों के बीच अपने जासूस तैनात किये हैं जो तिब्बतियों में आपस में तो वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, तिब्बतवासियों और चीनी नागरिकों तथा तिब्बतवासियों और संबद्ध देशों के नागरिकों के बीच भी दूरियां पैदा करने में जुटे हैं। इस तरह चीन तिब्बतियों के बीच की एकता और एकजुटता तथा उनके आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करने में जुटा है। इन सब चीजों का ध्यान रखकर सभी तिब्बतियों को काफी सावधान रहने की जरूरत है।

निर्वासित तिब्बतियों के आंदोलन के आधार वे मेजबान देश हैं, जहां वे लोग रहते हैं। खासकर, भारत जहां पर परमपावन दलाई लामा का निवास स्थल है और केंद्रीय तिब्बत प्रशासन (सीटीए) का कार्यस्थल है। इसलिए हम जब कभी कोई भी छोटा

चीन के नेताओं ने कहा है कि वे तिब्बत में प्रदर्शनों के खिलाफ 'जीवन और मृत्यु' की हद तक जाकर उसे कुचल देंगे। चीनी नेताओं के इस बयान ने उन की इस अंदरूनी असलियत को सामने ला दिया है कि ये नेता तिब्बतियों को चीन के बड़े परिवार का हिस्सा न मानकर उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं।

फोटो : विजय क्रान्ति

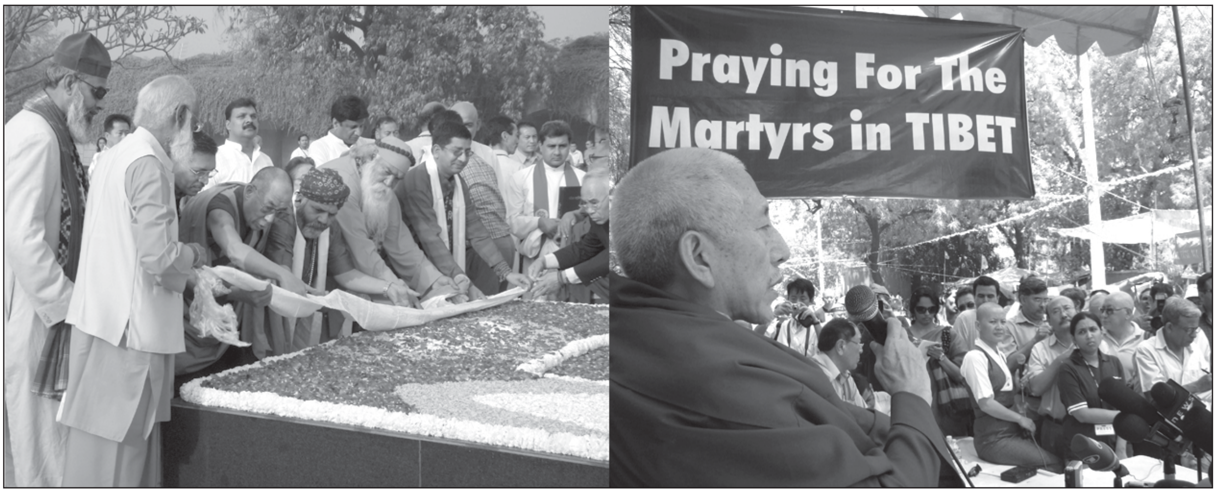

तिब्बती शहीदों के लिए सर्वधर्म प्रार्थनासभा में राजघाट पर दलाई लामा और जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे

हमें इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारी गतिविधियां संबद्ध मेजबान देशों के कायदे–कानूनों के खिलाफ नहीं हों। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना होगा जिससे संबद्ध देशों के लोगों को शर्मनाक स्थिति या अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े।

या बड़ा कदम उठाते हैं तो हमें इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारी गतिविधियां संबद्ध मेजबान देशों के कायदे–कानूनों के खिलाफ नहीं हों। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे संबद्ध देशों के लोगों को शर्मनाक स्थिति या अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके अलावा हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि अहिंसा के सिद्धांतों के तहत उठाये गये हमारे कदम हमारी कमजोरी नहीं, मजबूती है।चूंकि चीन ने हाल के घटनाक्रमों को तिब्बतियों और चीनी नागरिकों तथा विभिन्न धर्मों के बीच का संघर्ष बताने का प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन हमें उचित समय पर इस दुष्प्रचार का जवाब देने में सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए।

11. सभी तिब्बतियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के अलावा अच्छे धरम–करम भी करने चाहिएं ताकि उनका सामूहिक ज्ञान भी बढ़े। खासकर हमें डोल्मा, शेर–नीइंग, यीग–द्रुग और गुरुई थुग–डम ने–कुल की प्रार्थना कर परमपावन दलाई लामा की सलाह माननी चाहिए तथा इससे प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल तिब्बतियों को दमन से तत्काल मुक्त कराने, श्री अवलोकितेश्वर की परीक्षा भूमि में जान गंवाने वालों के शुभ पुनर्जन्म तथा घायलों के स्वस्थ होने एवं तिब्बत मसले के हल के लिए किया जाना चाहिए, ताकि तिब्बत के भीतर और बाहर रहने वाले तिब्बतवासी अपने एकीकरण का समारोह एक साथ मना सकें।

12. यह भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन है कि तिब्बत के भीतर जारी मौजूदा संकट भविष्य में कौन सा रूप लेगा। ऐसा भी संभव है कि हमलोगों को तिब्बत के भीतर और बाहर लंबे समय तक अभियान चलाते रहना पड़े। यह भी संभव है कि हमें कुछ राहत कार्यों में भी भाग लेना पड़े। इसलिए, परमपावन दलाई लामा के पिछले जन्मदिन पर जैसा कि कषाग ने अपील की थी कि सभी निर्वासित तिब्बतियों को, चाहे वे अमीर हों या गरीब, यथासंभव कम से कम खर्च करना चाहिए और अपनी आय का एक हिस्सा सामुदायिक कार्यों के लिए अलग रख छोड़ना चाहिए।

13. अंत में, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जैसी आशाएं परमपावन दलाई लामा ने अपने ज्ञान के माध्यम प्राप्त सलाह और मार्गदर्शन के रूप में हमें दी हैं उससे बड़ी पूंजी तिब्बत के लोगों के पास नहीं है। इस तरह की संकट की स्थिति में उनकी सलाहों पर हमें पूरे दिल से अमल करना चाहिए। इसके उलट, यदि हम दलाई लामा से बेहतर उपाय करने के नामपर निर्वासित तिब्बतियों की एकता को नजरअंदाज करते हैं तो हम इससे अपने दुश्मनों को खुशी पहुंचाते हैं और अपने दोस्तों को निराश करते हैं।

काशाग हाल के कुछ अभियानों से बहुत अधिक निराश है। इसके बावजूद हम उम्मीद व्यक्त करते हैं कि इस तरह के अभियान चलाने वालों की निष्ठा में कोई खोट नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये अभियान शुरू किये गये उससे यह संकेत मिलता है कि आयोजकों ने जानबूझकर परमपावन दलाई लामा को बदनाम करने और परेशान करने का प्रयास किया है। हमारा मानना है कि यह तिब्बत के मसले में मददगार साबित नहीं होगा।

(मूल तिब्बती भाषा में काषाग द्वारा जारी बयान के अंग्रजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर)

तिब्बती जनता ने चीनी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया

पूरे तिब्बत में प्रदर्शन। इंटरनेट और मोबाइल फोन से तिब्बत की सच्चाई पहली बार दुनिया के मीडिया पर

हालांकि 10 मार्च के दिन तिब्बत में हर साल कहीं न कहीं चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। लेकिन इस साल के प्रदर्शनों ने चीन सरकार को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। अगर एक ओर चीन सरकार ने तिब्बती जन क्रान्ति को कुचलने के लिए अपनी पूरी सैनिक और पुलिस ताकत को तिब्बत में झोंक दिया है तो दूसरी ओर दुनिया भर के मीडिया ने भी इन चीनी अत्याचारों की ओर सरकारों और मानवाधिकार संगठनों का ध्यान खींच कर तिब्बत की औपनिवेशिक त्रासदी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है।

अब तक के समाचारों के अनुसार चीनी सेना की गोलियां आजादी के दीवाने कम से कम 140 तिब्बती नागरिकों की जान ले चुकी हैं। हजार से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होकर चोरी छिपे इलाज के अभाव में मरने का खतरा झेल रहे हैं और कई हजार तिब्बतियों को चीनी जेलों में ठूंसा जा चुका है। लेकिन चीन सरकार की इस आतंककारी नीति के बावजूद चीन विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला न केवल जारी है बल्कि वह चीन के सिचुआन, युन्नान, गांसू और चिंघाई प्रांतों के उन तिब्बती इलाकों तक फैल चुका है जिन्हें चीन सरकार ने तिब्बत से काटकर चुपचाप इन चीनी प्रांतों में मिला लिया था।

अगले पांच महीने के भीतर बीजिंग में ओलंपिक खेलों के आयोजन को देखते हुए इन प्रदर्शनों और इनके जवाब में अमानवीय चीनी सैनिक कार्रवाई ने बीजिंग ओलंपिक के भविष्य पर एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है।

10 मार्च के दिन तिब्बत में चीन विरोधी प्रदर्शनों का यह सिलसिला 1959 से जारी है जब इसी दिन तिब्बत की जनता ने वहां 1950 से जबरन कब्जा जमाए बैठी विदेशी चीनी सेना के खिलाफ झंडा उठा लिया था। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार इस जनउभार को कुचलने के लिए चीनी सेना ने कम से कम 80 हजार तिब्बतियों की हत्या कर दी थी। खुद तिब्बत के शासक और धर्मगुरू दलाई लामा को तब अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी।

इस साल के प्रदर्शनों की शुरुआत 10 मार्च को ल्हासा के मुख्य मंदिर जोखांग की परिक्रमा बारखोर में 7 भिक्षुओं के प्रदर्शन और पुलिस द्वारा तुरंत उनकी बुरी तरह मार पिटाई से हुई। इसके बाद प्रदर्शनों का सिलसिला ल्हासा की परिधि पर मौजूद दो मुख्य मठों ड्रेपुंग और सेरा तक फैल गया जहां गिरफ्तारियों और भिक्षुओं तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ों ने गंभीर रूप ले लिया। अगले दिन ल्हासा से 60 किमी दूर बसे और राजनीतिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील माने जाने वाले गंदेन मठ में भिक्षुओं और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। इस बीच पूरे ल्हासा शहर को सेना ने घेरकर शहर की नाकेबंदी कर दी जिससे पैदा हुए तनाव ने तीन दिन बाद भयंकर प्रदर्शनों, आगजनी और हिंसक मुठभेड़ों का सिलसिला शुरू कर दिया।

इस बीच चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का यह सिलसिला पूरे 'टार' के अलावा तिब्बत के खम और आम्दो प्रांतों में भी फैल चुका था। चीन सरकार हर साल ल्हासा और शिगात्से जैसे शहरों के लिए तो तैयार रहती थी लेकिन इस बार धुर पश्चिम के रुथोक से लेकर शिगात्से, साक्या, सामये, फेन्पो, दामशुंग नागचू और पूर्व में मरखाम, गोंजो और जाम्दा में भी जमकर टकराव हुआ। लेकिन चीन सरकार के हाथ पांव तब फूल गए जब युन्नान, सिचुआन, गांसू और चिंघाई के चीनी प्रांतो में तिब्बती आबादी वाले 35 से ज्यादा स्थानों पर चीन विरोधी और दलाई लामा के समर्थन में प्रदर्शनों और दंगों का एक नया क्रम शुरू हो गया।

हालांकि इससे पहले चीन सरकार हर साल ऐसे प्रदर्शन को पुलिस और खुफिया एजेंसी पीएसबी की मदद से आसानी से दबा लेती थी और इसकी खबर तिब्बत में या बाहर किसी को भी नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार पचास से ज्यादा स्थानों पर एक साथ उठे जनउभार और प्रदर्शनकारियों द्वारा मोबाइल फोन, इंटरनेट और यूट्यूब के इस्तेमाल ने पूरे चीनी खेल को चौपट कर दिया। इससे पहले कि चीन सरकार कुछ कार्रवाई करती, प्रदर्शनो की लाइव फुटेज, पुलिस गोली से मारे गए लोगों की तस्वीरों और मोबाइल से भेजे गए समाचारों ने पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 16 मार्च के दिन ल्हासा से ढाई हजार किमी दूर कीर्ति मठ के एक भिक्षु ने धर्मशाला के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेस सम्मेलन से लाइव बात करके दिखा दिया कि नई टैक्नोलॉजी ने चीनी उपनिवेशवाद के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है।

इन प्रदर्शनों का विस्तृत विवरण 'तिब्बत देश' के अप्रेल अंक में दिया जाएगा।

इससे पहले कि चीन सरकार कुछ कार्रवाई करती, प्रदर्शनो की लाइव फुटेज, पुलिस गोली से मारे गए लोगों की तस्वीरों और मोबाइल से भेजे गए समाचारों ने पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 16 मार्च के दिन ल्हासा से ढाई हजार किमी दूर कीर्ति मठ के एक भिक्षु ने धर्मशाला के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेस सम्मेलन से लाइव बात करके दिखा दिया कि नई टैक्नोलॉजी ने चीनी उपनिवेशवाद के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है।

कैमरे की अ

1. सिचुआन प्रांत (खम) के कीर्ति मठ में चीनी पुलिस की गोलियों से मरे 15
2. तिब्बत में उभरे जन आंदोलन के समर्थन में भारत और विश्व भर में तिब्
3. तिब्बती भाई–बहनों के लिए भारतीय समर्थकों ने अभूतपूर्व एकजुटता दिख
4. तिब्बत में हुए चीन विरोधी प्रदर्शनों में 140 से अधिक लोग चीनी पुलिस
5. तिब्बत में प्रदर्शनकारियों पर चीन के अमानवीय अत्याचारों का परिचय दे
6. तिब्बत में चीनी सेना के हाथों मारे गए 140 से ज्यादा तिब्बती प्रदर्शनका
7. तिब्बत में चीनी अत्याचारों के विरोध में दिल्ली के तिब्बती समाज और भा
8. सभी तिब्बती संगठनों द्वारा संयुक्त आंदोलन चलाने की घोषणा करते हुए
9. तिब्बत के शहीदों को शांति और चीनी शासकों को सद्बुद्धि के लिए दिल
10. बीजिंग ओलंपिक के कला सलाहकार आर्नोल्ड श्वात्ज़नेगर द्वारा बहिष्कार

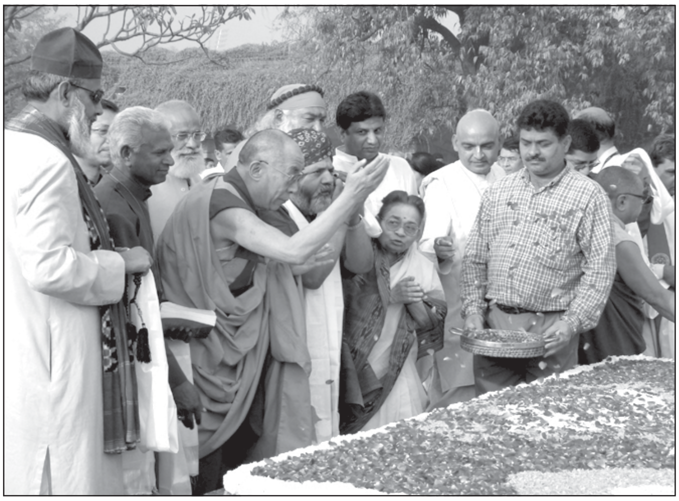

आंखों देखी

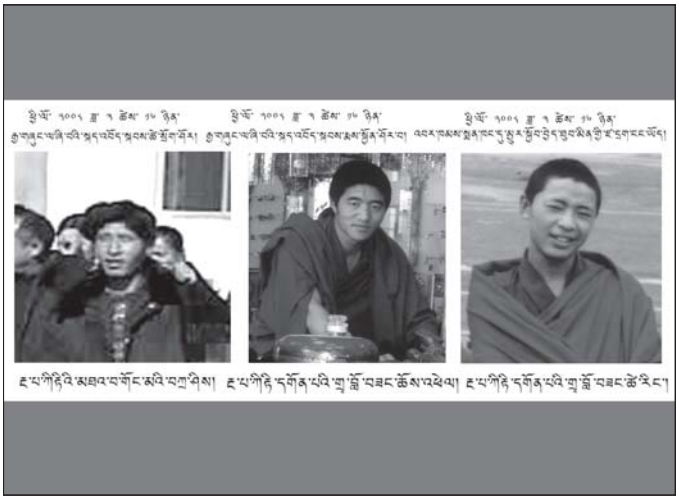

ांख से तिब्बत

5 तिब्बती प्रदर्शकारियों के शवों के पास खड़े स्थानीय नागरिक।

बतियों और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किए। जंतर मंतर में तिब्बती अनशनकारी।

ब्राई। भारत भर में हुए सैंकड़ों प्रदर्शनों में से एक में हिमालय परिवार कार्यकर्ता।

की गोलियों का शिकार हुए। ऐसे तीन युवा शहीद तिब्बतियों के फोटो।

ने के लिए दिल्ली में तिब्बती युवाओं ने इन अत्याचारों का मंचन किया।

रियों की याद में दिल्ली में तिब्बती समाज ने 140 शहीदों की शवयात्रा निकाली।

रतीय समर्थकों ने एक महीने से लंबे अनशन और प्रार्थना का आयोजन किया।

तिब्बती प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे संसद के अध्यक्ष व उपाध्यक्षा के साथ

ली में दलाई लामा ने सभी धर्मों के गुरुओं के साथ राजघाट पर प्रार्थना सभा की।

घोषणा के बाद हॉलिवुड अभिनेत्री उमा थुरमान ने भी बहिष्कार का फैसला किया।

तिब्बत में नई जनक्रान्ति

आखिर तिब्बती जनता की चीन सरकार से नाराजगी क्या है?

मार्च में शुरू हुए अभूतपूर्व तिब्बती जन आंदोलन के पीछे मौजूद कारणों का एक विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार और तिब्बत–विशेषज्ञ **विजय क्रान्ति** की कलम से

खम और आम्दो के पुराने अनुभव के बाद अब 'स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र' की जनता को डर सता रहा है कि लाखों की संख्या में हान चीनियों को 'टार' में बसाकर बीजिंग सरकार यहां भी तिब्बती समस्या का 'अंतिम हल' निकालने में लगी हुई है। ऐसे में अगर आज के तिब्बती युवाओं का गुस्सा ल्हासा या लिथांग के चीनी बैंकों और पुलिस के ट्रकों पर उतरता है तो इस गुस्से के कारणों को समझा जाना जरूरी है।

इन दिनों तिब्बत में चलने वाले घटनाचक्र ने अचानक वहां से आने वाली खबरों की रंगत को एकदम पलट दिया है। दुनिया भर के टीवी, इंटरनेट और अखबारों में तिब्बती जनता के गुस्से भरे प्रदर्शनों और उनके मुकाबले में लगे चीनी सेना के काफिलों को देखकर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि चीन सरकार द्वारा 'धरती के स्वर्ग' की तरह पेश किया जा रहा तिब्बत अचानक रातों–रात धरती का नरक कैसे बन गया?

पिछले कुछ साल से जब–जब भारतीय पत्रकार चीनी दूतावास के न्यौते पर तिब्बत की यात्रा करके लौटते हैं तो वहां चीन द्वारा किए गए विकास के किस्से सुनाते नहीं थकते। ल्हासा शहर में शानदार मल्टी स्टोरीड भवनों के ब्लाक, चौड़ी और तरतीब वार चौराहों वाली सड़कों पर दुनिया भर की महंगी कारें, बिजली की रोशनी में नहाए और रंगबिरंगे सामान और ग्राहकों से पटे हुए लकदक मॉल्स और दुनिया के आठवें अजूबे जैसी आधुनिक रेलगाड़ी .....। फोटोग्राफी के लिए तिब्बत की खुद अपनी दो यात्राओं के बाद मेरी भी राय है कि ल्हासा के मॉल्स जैसी चमक दमक पाने में दिल्ली को अभी भी दस–बीस साल इंतजार करना होगा।

10 मार्च को शुरू हुए प्रदर्शनों की फुटेज में तिब्बत के विकास से अभिभूत लोगों को यकीनन यह देखकर हैरानी हुई होगी कि तिब्बत के युवा प्रदर्शनकारी उन्हीं मॉल्स, दुकानों, बैंकों और कारों में आग लगा रहे थे जिन्हें चीन का प्रचारतंत्र तिब्बत के आधुनिक विकास के प्रमाण के रूप में चीनी जनता की ओर से तिब्बती जनता को दी गई भेंट के रूप में पेश करता आ रहा था।

और अब तो यह आंदोलन ल्हासा और दूसरे तिब्बती शहरों की सीमा को लांघकर चीन के युन्नान, सिचुआन, गांसू और चिंघाई जैसे उन प्रांतों के तिब्बती इलाकों में भी फैल गया है जिन्हें चीन सरकार तिब्बत का हिस्सा भी मानने को तैयार नहीं हैं। लिथांग, कीर्ति, सेरथार, लाबरांग और कारज़े जैसे दर्जनों शहरों–कस्बों से आने वाली खबरों से पता चलता है कि इन इलाकों के तिब्बती आक्रोश को दबाना चीन के लिए इस कारण बहुत मुश्किल हो गया है कि यहां रहने वाले तिब्बतियों को भी इंटरनेट, मोबाइल, टेलिफोन और आने जाने की वे सभी सुविधाएं लंबे समय से मिली हुई हैं जो वहां के चीनी नागरिकों को मिली हुई हैं। यही कारण है कि कीर्ति मठ में 16 मार्च को चीनी सेना की गोलीबारी में मारे गए 15 तिब्बती प्रदर्शनकारियों के शवों के फोटो कुछ मिनट में पूरी दुनिया के टीवी चैनलों तक पहुंच गए।

यहां यह जानना रोचक होगा कि 1951 में तिब्बत पर कब्जा जमाने के तुरंत बाद चीन ने तिब्बत के दो पूर्वी प्रांतों आम्दो और खम को तिब्बत से काटकर उपरोक्त चार चीनी प्रांतों में मिला दिया था। बाकी बचा हुआ एक तिहाई तिब्बत वही है जिसे चीन सरकार आज 'टिबेट ऑटोनामस रिजन' (टार) के नाम से असली तिब्बत के तौर पर तरह पेश कर रही है। उस समय तिब्बत की कुल जनसंख्या लगभग 60 लाख थी जबकि पूरे तिब्बत का क्षेत्रफल आज के चीन के एक चौथाई से ज्यादा है। चीन के जनसंख्या विभाग के 2002 के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार इन चार प्रांतों की कुल जनसंख्या 15 करोड़ से ऊपर है जिसमें से तिब्बतियों की आबादी केवल 35 लाख है।

खम प्रांत के ग्यालथांग और आम्दो के सिलिंग शहरों की अपनी यात्रा के दौरान मैंने पाया था कि तिब्बती 'शांग्रीला' के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पेश किए जा रहे ग्यालथांग में आज एक तिब्बती के मुकाबले कम से कम सौ चीनी नागरिक वहां बस गए हैं। सिलिंग में मुझे पहला तिब्बती देखने से पहले किसी बड़ी सड़क पर खड़े होकर कम से कम पांच सौ चीनी नागरिकों के गुजरने का इंतजार करना पड़ा। ल्हासा में भी अपनी दो यात्राओं में मैंने पाया कि दो साल के अंतर में ही वहां के सभी मलाईदार स्थानों से तिब्बती भिखारी गायब हो चुके थे और उनके ठीयों पर चीनी भिखारियों ने कब्जा जमा लिया था। तिब्बत में चीन से लाकर बसाए जा रहे हान चीनियों ने ल्हासा शहर पर इस कदर कब्जा जमा लिया है कि वहां के मॉल्स और बड़ी दुकानों पर तिब्बती भाषा में खरीदारी तक नहीं की जा सकती।

खम और आम्दो के पुराने अनुभव के बाद अब 'टार' (स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र) की जनता को सबसे बड़ा यही डर सता रहा है कि लाखों की संख्या में हान चीनियों को 'टार' में बसाकर बीजिंग सरकार खम और आम्दो की तरह यहां भी तिब्बती समस्या का 'अंतिम हल' निकालने में लगी हुई है। ऐसे में अगर आज के तिब्बती युवाओं का गुस्सा ल्हासा या लिथांग के चीनी बैंकों और पुलिस के ट्रकों पर

उतरता है तो इस गुस्से के कारणों को समझा जाना जरूरी है।

दो साल पहले चीनी शासक तिब्बत में चीनी रेलगाड़ी को तिब्बती जनता के लिए एक महान सौगात के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन आम तिब्बती को समझ में आ रहा है कि इस रेलगाड़ी के शुरू होने पर अब ठेके और नौकरियां पाने के लिए आए हुए चीनी नागरिकों को अपने परिवार से मिलने के लिए चार दिन की थकाऊ बस यात्रा नहीं करनी पड़ती। अब वे चौबीस घंटे की रेल सवारी करके अपने पूरे परिवार को तिब्बत में बसाने के लिए अपने साथ ला सकते हैं। 20 मार्च के दिन जब बीबीसी के पत्रकार ने गांसू से ल्हासा के लिए निकली रेलगाड़ी पर दर्जनों फौजी टैंकों और फौजी गाड़ियों को दिखाया तब उन लोगों को चीनी रेलगाड़ी की असलियत समझ आई जो अब तक रेलगाड़ी पर तिब्बतियों और उनके समर्थकों की नाराजगी का मजाक बनाते आ रहे थे।

तिब्बत में प्रदर्शनों यह नया दौर अपनी तरह का पहला नहीं है। अंतर केवल इतना है कि दूर संचार की क्रांति ने अब तिब्बतियों को न केवल आपसी संपके की सुविधा उपलब्ध करा दी है बल्कि पर्यटन से टूरो–डालरों चीनी भूख ने उन्हें बाकी दुनिया के साथ जुड़ने की सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी हैं।

1989 में जब इसी तरह का जन उभार ल्हासा में शुरू हुआ था तब कुछ पर्यटकों की खींची सीमित तस्वीरों के अलावा दुनिया को इसके बारे में बहुत कुछ देखने को नहीं मिल पाया था। तब तिब्बत के गवर्नर पद पर बैठे श्री हू जिंताओं ने अपनी गर्दन और गद्दी बचाने के लिए फौजी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से सैंकड़ों निहत्थे नागरिकों को मारकार जनक्रान्ति के इस सैलाब को आसानी से दबा दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री हू जिंताओ द्वारा तिब्बत में अपनाए गए इसी 'ल्हासा माडल' का इस्तेमाल बीजिंग के थिएन अनमन चौक में चीनी युवाओं के आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया था। जिंताओ के इसी योगदान ने उन्हें चीनी नेतृत्व की आंखों में चढ़ाया और आज उन्हें राष्ट्रपति के पद तक पहुचाया है।

तिब्बत में जनविरोध को कुचलने के लिए हिंसा के इस्तेमाल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना वहां पर चीन के कब्जे का है। 1956 से 1959 के बीच तिब्बत के पूर्वी हिस्से के खम, आम्दो और गोलोक में उभरे सशस्त्र आंदोलन को कुचलने के लिए चीनी सेना ने हवाई जहाजों से मशीनगन की फायरिंग और बमबारी जैसे कदम भी उठाए थे जिनका विस्तृत विवरण अमेरिकी पत्रकार माइकेल डनहाम ने अपनी ताजा पुस्तक 'बुद्धाज़ वारियर्ज' में दिया है। 1960 में संयुक्त राष्ट्र के न्यायविदों के आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 1959 में चीनी सेना के खिलाफ तिब्बती जन उभार को कुचलने के लिए चीनी सेनाओं ने लगभग 80 हजार तिब्बतियों की हत्या की थी। बाद के वर्षों में चीन से भी ज्यादा लंबी 'कल्चरल रेवोल्यूशन' के दौरान हुई हिंसा, 'जन अदालतों' और अकाल के कारण तिब्बत में जो लोग अकाल मौत का शिकार हुए उनकी संख्या 12 लाख से ज्यादा मानी जाती है।

ताजा प्रदर्शनों में पुलिस की गोली से मारे गए तिब्बतियों की संख्या के बारे में चीन सरकार का कहना है कि केवल 13 लोग मारे गए हैं। विदेशी मीडिया ने इसे 80 के आसपास बताया जबकि तिब्बत पर बारीकी से नजर रखने वाले तिब्बती और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि उनके पास 140 ऐसे लोगों के नाम पते हैं जो चीनी पुलिस और सेना के हाथों मारे गए हैं। चीनी गोलियों से घायल ऐसे लोगों की संख्या सैंकड़ों में है जिन्हें अस्पतालों ने इलाज उपलब्ध कराने से मना कर दिया या जो गिरफ्तारी के डर से अस्पताल जाने से डर रहे हैं। इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दर्जनों संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व समाज से अपील की है कि तिब्बत की असली हालत को जानने और गोली से घायल सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राहत और अध्ययन दल तिब्बत के प्रभावित इलाकों में भेजा जाना चाहिए।

तिब्बती जनता की शिकायतों के पुलंदे में चीन के जनसंख्या हथियार के अलावा तिब्बती संस्कृति और पहचान को नियोजित तरीके से नष्ट करने, तिब्बती युवाओं को जबरन चीन लेजाकर उन्हें अपनी संस्कृति से परे करने और राजनीतिक ब्रेन वाशिंग करने, तिब्बत के संसाधनों की लूट और चीनी व्यवस्था में तिब्बतियों को अपने ही देश में अर्थहीन बना डालने जैसी ढेरों शिकायतें हैं। आज का तिब्बती जन उभार इन सभी शिकायतों का नवीनतम विस्फोट है। चीनी नेतृत्व के सामने अब केवल दो रास्ते हैं। या तो वह तिब्बती जनता की शिकायतों को समझकर बातचीत के रास्ते उनका हल निकालने का साहस दिखाए या फिर इस विस्फोट को चीन के उन नाराज वर्गों तक पहुंचने का रास्ता साफ करे जो आर्थिक असंतुलन, लोकतंत्र की मांग और फालुन गांग तथा मुस्लिम औरईसाई संगठनों पर चीनी सरकार के शिकंजे के कारण पहले से ही सूखे बारूद की तरह तैयार बैठे हैं।

आज का तिब्बती जन उभार इन सभी शिकायतों का नवीनतम विस्फोट है। चीनी नेतृत्व के सामने अब केवल दो रास्ते हैं। या तो वह तिब्बती जनता की शिकायतों को समझकर बातचीत के रास्ते उनका हल निकालने का साहस दिखाए या फिर इस विस्फोट को चीन के उन नाराज वर्गों तक पहुंचने का रास्ता साफ करे जो आर्थिक असंतुलन, लोकतंत्र की मांग और फालुन गांग तथा मुस्लिम औरईसाई संगठनों पर चीनी सरकार के शिकंजे के कारण पहले से ही सूखे बारूद की तरह तैयार बैठे हैं।

फोटो : विजय क्रान्ति

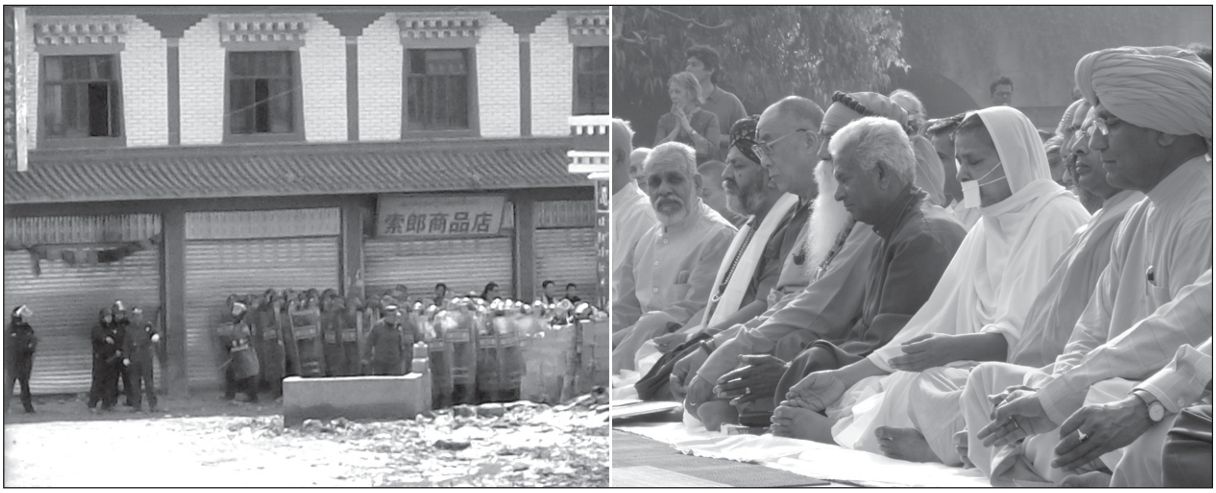

कीर्ति में तैनात चीनी पुलिस (बाएं) और तिब्बती शहीदों के लिए प्रार्थना सभा में दलाई लामा के साथ भारत के विभिन्न धर्मों के वरिष्ठ नेता

तिब्बत में चीन सरकार के षडयंत्रों पर विश्व जनमत ध्यान दे

तिब्बत की स्थिति पर कालोन ट्रीपा (तिब्बत निर्वासन सरकार में प्रधानमंत्री के समकक्ष) प्रो. सामदोंग रिंपोछे का प्रेस वक्तव्यः

ये विरोध प्रदर्शन पिछले पांच दशक से हो रहे दमन के कारण तिब्बतियों के दिल में गहरे जड़ जमा चुके असंतोष और 10 मार्च को तिब्बती क्षेत्रों में भिक्षुओं एवं आम लोगों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने का परिणाम हैं।

(तिब्बत में नए उभरे जनआंदोलन ने चीन सरकार के लिए जितने बड़े पैमाने पर अंतर्राश्ट्रीय संकट खड़ा किया है वैसा पिछले चालीस साल में कभी देखने में नहीं आया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार चीन ने वहां 140 से ज्यादा तिब्बतियों की हत्या की है। इस बदनामी के जवाब में चीन ने जो प्रोपेगेंडा अभियान चलाया है, प्रो. रिंपोछे का यह बयान उसी की ओर ध्यान दिलाता है – संपादक)

10 मार्च 2008 से ही ऊ–त्सांग, खम और आम्दो के सभी क्षेत्रों एवं चीन के उन क्षेत्रों में, जहां तिब्बती निवास करते हैं, व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। ये विरोध प्रदर्शन पिछले पांच दशक से हो रहे दमन के कारण तिब्बतियों के दिल में गहरे जड़ जमा चुके असंतोष और 10 मार्च को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के भीतर और बाहर अनेक स्थानों पर भिक्षुओं एवं आम लोगों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने का परिणाम हैं।

10 मार्च का दिन तिब्बतियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रत्येक वर्ष उस दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ करता है, लेकिन यह प्रदर्शन एक ही दिन होता रहा है। किन्तु इस वर्ष चीन की अनावश्यक दमनात्मक कार्रवाइयों और ताकत के इस्तेमाल के कारण ये विरोध प्रदर्शन कई दिनों तक लगातार होते रहे।

यदि बल प्रयोग का चीनी अधिकारियों का उद्देश्य तिब्बत में शांति व्यवस्था कायम करना होता तो यह एक दिन के भीतर ही हो गया होता, लेकिन पांच सप्ताह तक स्थिति सामान्य नहीं हुई और दिन–ब–दिन विरोध प्रदर्शन तथा उन्हें कुचलने के चीनी अधिकारियों के प्रयास जारी हैं। अनेक संदिग्ध घटनाओं में से निम्नांकित कुछ ऐसी खास घटनाएं हैं जिन्हें रेखांकित किया जाना जरूरी हैः–

1. 14 मार्च को ल्हासा में अनेक घंटों तक विरोध प्रदर्शनों को अनुमति दी गयी और अधिकारियों ने कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाए।

2. उस दिन की हिंसक गतिविधियों में शामिल अनेक प्रदर्शनकारियों से स्थानीय लोग अपरिचित थे। ऐसे भी कई मामले हैं जहां लोगों ने चीनी पुलिसकर्मियों को तिब्बतियों की पोशाकों और भिक्षुओं के वेश में देखा गया जो प्रदर्शन के दौरान नेतृत्वक करने वालों की भूमिका में दिखाई दिए।

3. चीनी अधिकारियों का दावा है कि उन्हें कुछ मठों से बंदूकें और गोलियां मिली हैं। यह दावा मठों से बरामद देशी बंदूकों और तलवारों के आधार पर किया गया जो सुरक्षा की देवी (गोनखांग) के पास से बरामद किये गये हैं। कुछ मामलों में तो सैन्यकर्मी ही मठों में हथियार और असलाह लेकर आए थे। बाद में उन्होंने दावा किया कि ये हथियार मठों से बरामद किये गये हैं। उन्होंने इसका इलजाम तिब्बतियों के सिर ही मढ़ दिया है।

4. चीनी अधिकारियों ने दावा किया है कि तिब्बत को आजाद कराने वाली ताकतें आत्मघाती हमलों की योजना बना रही हैं।

5. उन्होंने पूर्वी तिब्बत के चाम्दो में कुछ भिक्षुओं पर बम विस्फोट कराने का भी आरोप लगाया है, जिसकी वजह से वहां कथित रूप से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन चीनी अधिकारी

अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाए हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती हो।

6. देशभक्ति का 'पुनर्शिक्षा अभियान' फिर से शुरू किया गया है और मठों और लोगों को अपने भवनों पर चीनी राष्ट्रध्वज फहराने के निर्देश दिये गए हैं।

7. हर जगह परमपावन दलाई लामा के खिलाफ अभियान को सख्ती से चलाया जा रहा है। इससे तिब्बतियों की भावनाएं आहत होती हैं।

8. चीन सरकार तिब्बतवासियों और चीनवासियों के बीच गतिरोध पैदा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। ऐसा चीनी राष्ट्रवाद के नाम पर और आम चीनवासियों में दलाई लामा के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए किया जा रहा है।

इन कदमों से तिब्बत में मानसिक शांति और सामाजिक व्यवस्था कायम करने में मदद नहीं मिल सकती है। इसके विपरीत तिब्बती नागरिक इन कदमों को उकसाने वाला मानते हैं क्योंकि इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी गतिविधियां तिब्बतियों की सहनशीलता को नजरअंदाज करने और उन्हें उकसाने के इरादे से की जा रही हैं ताकि तिब्बती नागरिक इसका किसी प्रकार से हिंसक प्रतिकार करने पर उतारू हों। ऐसे भी संकेत हैं कि चीन सरकार की विभिन्न एजेंसियां कुछ और बम विस्फोट करने और अन्य विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने और इसका ठीकरा निर्दोष तिब्बतियों के सिर पर फोड़ने की योजना बना रही हैं।

हम तिब्बती नागरिकों की निर्मम पिटाई, उत्पीड़न, हत्या और भोजन पानी से वंचित रखने जैसी दमनात्मक कार्रवाइयों से काफी आहत हैं। हम इस बात से भी काफी आहत हैं कि ये दमनात्मक कार्रवाइयां आने वाले कई महीनों तक जारी रहेंगी।

तिब्बत को पूरी तरह सील कर दिया गया है और कुछ दिनों के भीतर ही चीनी अधिकारी निर्दोष तिब्बतियों को सजा सुनाकर सभी साक्ष्यों को खत्म कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और चीनी अधिकारियों को अत्याचारी कदम रोकने के लिए राजी कराना चाहिए। तिब्बत की स्थिति लंबे समय से खराब चल रही है और इसके लिए चीन सरकार द्वारा 1957–58 के दौरान शुरू की गयी कट्टर वामपंथी नीतियां जिम्मेदार हैं। इन्हीं नीतियों के कारण 10 मार्च 1959 को चर्चित तिब्बती जनक्रान्ति शुरू हुई थी। उसके बाद से तिब्बतियों को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। दस लाख से अधिक तिब्बती लापता हो चुके हैं और स्थिति अब भी खतरनाक है। इस तरह की नीतियों का चीन में भी विरोध हुआ था। वहां तो इन्हें वापस ले लिया गया लेकिन तिब्बतियों के लिए इन नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तिब्बती नागरिकों के प्रति चीन सरकार की मौलिक नीतियों में जबतक परिवर्तन नहीं होगा, तबतक कोई भी ताकत तिब्बतियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है।

फोटो : विजय क्रान्ति

तिब्बती जनता के सर्थन में भारतीय तिब्बत मित्र : अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

चीनी नेतृत्व एक ओर तो यह मांग करता है कि परमपावन दलाई लामा तिब्बत में स्थिति सामान्य बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, वहीं दूसरी ओर वे तिब्बत में दलाई लामा को अपने प्रभाव के इस्तेमाल के लिए न तो कोई रास्ता दे रहे हैं और न कोई स्रोत। इसके उलट चीनी नेतृत्व तिब्बत में दलाईलामा के खिलाफ अभियान को और अधिक सशक्त करने में जुटा है।

चीनी नेतृत्व ने तिब्बत में अशांति के मूल कारण का पता लगाने और उसे खत्म करने की दिशा में प्रयास करने से इनकार कर दिया है। उल्टे वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं को और अधिक बढ़ाने में जुटे हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि वे तिब्बत में शांति और स्थायित्व नहीं चाहते हैं।

इसलिए, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील करते हैं कि वह तिब्बतियों के खिलाफ ऐसी जघन्य कार्रवाइयों में शामिल चीन सरकार को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तिब्बत की सांस्कृति विरासत को योजनाबद्ध तरीके से मिटाने की चीन सरकार की नीति को रोकने की दिशा में भी कदम उठाए।

प्रो. सामदोंग रिंपोछे,
कालोन ट्रीपा

चीनी नेतृत्व एक ओर तो यह मांग करता है कि दलाई लामा तिब्बत में स्थिति सामान्य बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, वहीं दूसरी ओर वे दलाई लामा को अपना प्रभाव इस्तेमाल के लिए न तो कोई रास्ता दे रहे हैं और न कोई स्रोत। इसके उलट चीनी नेतृत्व तिब्बत में दलाईलामा के खिलाफ अभियान को और अधिक सशक्त करने में जुटा है।

दलाई लामा की अपील पर पशुओं की खाल के कपड़ों की होली : नेता में आस्था

आम्दो में तिब्बतियों और चीनी पुलिस के बीच झड़प और गिरफ्तारियां

प्रार्थना समारोह में सरकारी दखल से लोग भड़के

आम्दो, 23 फरवरी पूर्वी तिब्बत के आम्दो प्रांत के सूत्रों ने चीनी अधिकारियों और वार्षिक प्रार्थना समारोह में शामिल होने के लिए एकत्रित सैकड़ों तिब्बतियों के बीच व्यापक संघर्ष की खबर दी है।

सूत्रों ने रेडियो फ्री एशिया (आरएफए) बताया कि चिंघाई प्रांत की रेबकांग काउंटी के अधिकारियों ने 21 फरवरी को प्रार्थना समारोह को रोकने के आदेश दिए, जिसका तिब्बतियों ने प्रतिरोध किया। इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में व्यापक संघर्ष हुआ। इसके बाद चीनी अधिकारियों ने मौके पर तीन ट्रक सशस्त्र सुरक्षा बल भेजे।

एक सूत्र ने रेडियो की तिब्बत सेवा को बताया, ''उन लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े।'' हिरासत में लिए गए 200 तिब्बतियों में से ज्यादातर उस क्षेत्र के बौद्ध भिक्षु थे जो प्रार्थना से जुड़े एक धार्मिक नृत्य समारोह में भाग ले रहे थे। हिरासत में लिए जाने की वजह से वे नृत्य नहीं कर सके।

इस वर्ष के कार्यक्रम को देखने के लिए वहां हजारों दर्शक पहुंचे थे। हाल के वर्षों में मोनलम समारोह में पटाखे भी चलाए जाते रहे हैं जो चीनी समारोहों में पटाखों की परंपरा का प्रभाव है। सूत्रों ने बताया कि भीड़ द्वारा चीन–विरोधी प्रदर्शन की आशंका से करीब 200 सशस्त्र और गैर–सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए थे। चीनी सुरक्षाकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या और उनकी मुस्तैदी ने लोगों को भड़काने की भूमिका निभाई। उनकी गतिविधियों से खफा तिब्बतियों का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उपस्थित भीड़ ने देखते–देखते सात सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे देखते हुए अधिकारियों ने और अधिक सुरक्षा बल भेजे और करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ज्यादातर भिक्षु हैं। बाद में भिक्षुओं में से ज्यादातर को रिहा भी कर दिया गया।

झड़प और विरोध प्रदर्शन के दौरान अनेक तिब्बतियों ने तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारेबाजी की और परमपावन दलाई लामा के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। तिब्बतियों का प्रदर्शन रात दस बजे तक जारी रहा।

एक अन्य सूत्र ने बताया, ''झड़प और विरोध प्रदर्शन के दौरान अनेक तिब्बतियों ने तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारेबाजी की और परमपावन दलाई लामा के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। तिब्बतियों का प्रदर्शन रात दस बजे तक जारी रहा।''

सूत्रों ने बताया कि जब पुलिस कुछ भिक्षुओं को हिरासत में लेकर चली गयी तो लोगों का विरोध और तेज हो गया। अगले दिन तिब्बतियों के व्यापक प्रदर्शन के दबाव में स्थानीय प्रशासन ने पिछले दिन के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गए लोगों को रिहा कर दिया। लेकिन हिरासत के दौरान उनमें से अनेक के साथ मार–पीट भी की गयी थी और उत्पीड़न किया गया था। उनमें से गंभीर रूप से घायल दो लोगों को इलाज के लिए जिनिंग ले जाया गया।

इस उत्पीड़न की खबरें फैलने के बाद तिब्बती प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ गया। अंत में रेबकांग मठ के मुख्य लामा ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद ही प्रदर्शन समाप्त हो सका। जब रेडियो फ्री एशिया ने टेलीफोन के माध्यम से रेबकांग पुलिस से जानकारी चाही तो उसने इसपर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

चीनी अधिकारी स्थानीय तिब्बतियों की नाराजगी को विघटनकारी काम मानते हैं और ऐसे मौकों पर कठोर कार्रवाई करते हैं। रेबकांग दो वर्ष पहले तिब्बतियों को जानवरों की खाल पहनने से मना करने के अभियान का केंद्र था। यह अभियान पिछले साल भारत के अमरावती में कालचक्र पूजा समारोह में परमपावन दलाई लामा की इस अपील के बाद शुरू हुआ था कि तिब्बतवासियों को जानवरों की खालों से बनीं पोशाकें पहननी बंद कर देनी चाहिएं। उनकी इस अपील के परिणामस्वरूप पूरे तिब्बत में बाघ, चीते और समुद्री उदबिलाव की खालों से बने वस्त्रों की सार्वजनिक होली जलाने का आंदोलन शुरू हो गया था। चीन सरकार ने इस आंदोलन को दलाई लामा के नाम पर चीन विरोधी आंदोलन मानते हुए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। यहां तक कि टेलीविजन पर तिब्बती प्रसारकों और एंकरों को ऐसी पोशाकें पहन कर टीवी कार्यक्रम पेश करने क आदेश जारी किए गए थे।

लंदन में प्रिंस चार्ल्स : कूटनीति पर नैतिकता का प्रभाव

ओलम्पिक समारोह में उपस्थित होने से प्रिंस चार्ल्स का इनकार

चीन सरकार की तिलमिलाहट भरी प्रतिक्रिया

बीजिंग, 28 जनवरी। प्रिंस ऑफ वेल्स (प्रिंस चार्ल्स) ने बीजिंग ओलम्पिक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने से इनकार कर चीन सरकार को एक जोरदार चपत लगाई है। 'फ्री तिब्बत कैम्पेन' संगठन ने यह जानकारी दी है। संगठन ने प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात कर तिब्बत आंदोलन में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आग्रह किया था।

प्रिंस के उप निजी सचिव क्लाइव एल्डर्टन ने फ्री तिब्बत कैम्पेन को लिखे पत्र में कहा है, "जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंस चार्ल्स लंबे समय से तिब्बत के मामले में गहरी रूचि रखते हैं और अनेक अवसरों पर परमपावन दलाई लामा से मिलकर निश्चित तौर पर उन्हें खुशी हुई है। आपने पूछा है कि क्या प्रिंस ऑफ वेल्स बीजिंग ओलम्पिक 2008 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रिंस इस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे।"

लेकिन प्रिंस ने न तो अपने फैसले का कारण ही बताया और न ही यह बताया कि क्या उन्हें औपचारिक निमंत्रण प्राप्त हुआ है।हाल के महीनों में चीन की ओर से, खासकर लंदन स्थित चीनी दूतावास की नवनियुक्त राजदूत उन्हें बीजिंग ओलम्पिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करती रही हैं। राजदूत कह चुकी हैं कि बीजिंग समारोहों में भाग लेने के लिए प्रिंस को प्रेरित करना उनका व्यक्तिगत मिशन था।

प्रिंस के कर्मचारियों ने अलग से भी यह स्पष्ट किया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स ओलम्पिक खेलों के किसी भी चरण में उपस्थित नहीं होंगे। फ्री तिब्बत कैम्पेन ने प्रिंस के फैसले का स्वागत किया है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा, "हम ओलम्पिक खेलों से प्रिंस चार्ल्स के अलग रहने के फैसले का स्वागत करते हैं। हम सार्वजनिक जीवन वाली अन्य हस्तियों से भी मिलकर उन्हें प्रिंस के नक्शे कदम पर चलने का आग्रह करेंगे।"

प्रवक्ता ने कहा, "ओलम्पिक खेलों की मेजबानी मिलने के बाद से चीन और तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति लगातार खराब हुई है और यहां होने वाले ओलम्पिक खेल 'गेम ऑफ शेम' के रूप में जाने जाएंगे।"

लेकिन प्रिंस के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि चीन के शहरी विकास संबंधी योजनाओं में प्रिंस की रुचि बनी रहेगी। प्रिंस चार्ल्स की ओर से चीन को सहयोग जारी रखने की घोषणा का एक कारण ब्रिटिश सरकार और प्रिंस के निजी सचिव सर माइकल पीट द्वारा यह चिंता जताया जाना है कि चीन के साथ प्रिंस चार्ल्स की दुश्मनी वैसे समय राजनीतिक कठिनाई पैदा कर सकती है, जब ब्रिटिश सरकार रिश्ते सुधारने की वकालत कर रही है।

चीन तिलमिलाया

प्रिंस चार्ल्स के इस कदम पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन ने कहा है कि प्रिंस चार्ल्स द्वारा ओलम्पिक खेलों के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना अनुचित होगा।

इस बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख–पत्र 'पीपुल्स डेली' ने कहा है कि बीजिंग ओलम्पिक के मुद्दे पर चीन को घेरना या सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए मजबूर करने का कोई भी प्रयास असफल रहेगा। मुखपत्र में प्रकाशित यह बयान चीन सरकार के नेताओं के बीच हताशा को प्रदर्शित करता है।

जनसम्पर्क विभाग की ओर से जवाबी बयान उस वक्त आया है जब ओलम्पिक आयोजकों की विभिन्न मुद्दों पर किरकिरी हो रही है। निर्माण स्थल पर हुई दुर्घटना और मशाल दौड़ के दौरान तिब्बत में होने वाले प्रदर्शन को दलाई लामा द्वारा समर्थन दिये जाने की खबरें आयोजन समिति के लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं।

मुखपत्र में लिखे लेख में कहा गया है कि चिल्ल पों मचाने से आयोजन समिति और बीजिंग ओलम्पिक की योजनाओं के समक्ष कुछ परेशानियां अवश्य आ सकती है, लेकिन चीन की साख घट नहीं सकती।

प्रिंस ऑफ वेल्स ओलम्पिक खेलों के किसी भी चरण में उपस्थित नहीं होंगे। फ्री तिब्बत कैम्पेन ने प्रिंस के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है हम अन्य सार्वजनिक हस्तियों से भी प्रिंस के नक्शे कदम पर चलने का आग्रह करेंगे।"

ताईपे में ओलंपिक मशाल के साथ पूर्व मिस तिब्बत सेरिंग चुंगताक : जनसमर्थन

तिब्बती आंदोलनकारियों ने ताईवान में सांकेतिक मशाल दौड़ आयोजित की

निर्वासित तिब्बती अपना ओलंपिक अलग से आयोजित करेंगे

ताईपे, 24 फरवरी (फरवरी)। ताईवान द्वारा चीन सरकार को अपने यहां ओलम्पिक मशाल दौड़ के आयोजन की अनुमति नहीं देने से आहत चीन सरकार को उस वक्त एक और झटका लगा जब तिब्बती समर्थक संगठनों ने यहां सांकेतिक मशालदौड़ का आयोजन किया।

स्थानीय 'ताईवान डेमोक्रैसी मेमोरियल हॉल' के सामने एक चौराहे पर तिब्बतियों और ताईवानियों का एक छोटा दल मौजूद था। उनमें से एक पारम्परिक पोशाक में लिपटी सुंदरी पूर्व मिस तिब्बत त्सेरिंग चुंगतक भी थीं जिन्होंने 'तिब्बती ओलम्पिक मशाल' थाम रखी थी। वहां एकत्रित समूह 'तिब्बती ओलम्पिक' ध्वज लहरा रहा था और तिब्बत के समर्थन में नारे लगा रहा था।

सुश्री त्सेरिंग ने संवाददाताओं से कहा कि दुनिया भर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे तिब्बतवासियों के तिब्बती ओलम्पिक खेल इस वर्ष मई में भारत के धर्मशाला में आयोजित किया जाएंगे। तिब्बती ओलम्पिक का आयोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम दुनिया के सामने अपनी राष्ट्रीय पहचान पेश कर पाएंगे। बाकी देशों के युवाओं की तरह हम भी खेल में रुचि रखते हैं। लेकिन तिब्बत के गुलाम होने के कारण उसे ओलंपिक से बाहर रखे जाने से हम सब आहत हैं।

तिब्बती ओलम्पिक खेल इस वर्ष मई में भारत के धर्मशाला में आयोजित किया जाएंगे। तिब्बती ओलम्पिक का आयोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम दुनिया के सामने अपनी राष्ट्रीय पहचान पेश कर पाएंगे।

चीन सरकार ताइवान को चीन का हिस्सा होने का दावा करती आ रही है और उसे जबरन चीन में शामिल करने की धमकियां भी देती रहती है। इसलिए ताईवान ने बीजिंग ओलम्पिक 2008 की मशाल दौड़ ताईपे में कराने के चीन के प्रस्ताव को उस वक्त ठुकरा दिया था जब बीजिंग सरकार ने मांग की कि ताइवान में मशाल दौड़ के दौरान केवल चीनी झंडा लहराया जाए और चीनी राष्ट्रगान गाया जाए।

अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ने तिब्बत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया

धर्मशाला, 29 जनवरी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ (आईयूएसवाई) की 27वीं विश्व कांग्रेस के दौरान तिब्बत पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें एक बार फिर तिब्बत को स्वतंत्र देश की संज्ञा दी गयी। साथ ही तिब्बत पर चीन के गैरकानूनी कब्जे की निंदा भी की गयी।

इस प्रस्ताव में पिछले वर्ष आईयूएसवाई की एशिया प्रशांत समिति की बैठक के दौरान जारी पांच सूत्रीय प्रस्ताव की पुष्टि की गयी है, जिसके कहा गया है कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है और चीन का उसपर अवैध कब्जा निंदनीय है।

आईयूएसवाई की तीन–दिवसीय विश्व कांग्रेस का समापन 27 जनवरी को डोमिनिकन रिपब्लिक के सेंटो डोमिनगो में हुआ। तिब्बत सहित 68 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने विश्व कांग्रेस में भाग लिया। कांग्रेस का उद्घाटन डोमिनिकन रिपब्लिक में राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक मिगुएल वर्गास मालडोनाडो ने 25 जनवरी को किया।

तिब्बतियों के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन तिबेतन यूथ कांग्रेस (टीवाईसी) के अध्यक्ष त्सेवांग रिगजिन ने आईयूएसवाई की विश्व कांग्रेस में तिब्बत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा 'पीपुल इन मूवमेंट' था।

प्रस्ताव में चीन की आबादी को तिब्बत में स्थानांतरित किये जाने संबंधी नीति समाप्त करने की मांग की गयी। दूसरे प्रस्ताव में चीन द्वारा तिब्बत में वहां की जनता को अर्थहीन अल्पसंख्यक बना देने की षडयंत्रकारी नीति की निंदा की गयी है।

सम्मेलन में नेपाल सरकार से भी अपील की गयी कि वह तिब्बती शरणार्थियों के प्रत्यर्पण की नीति समाप्त करे और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन के अनुरूप तिब्बत से भागकर सीमा पार करने वाले तिब्बतियों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराए।